

RAJYA SABHA

*Friday the Wth July 1998-19 Asadha, 1920
(Saka)*

The House met at Eleven of the clock Mr.
Chairman *in the Chair*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**Running of Fake Universitic in the
Country**

*341 SHRIMATI KAMLA SINHA:
SHRI JANARDAN YADAV:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the UGC has recently identified
a number of fake universities functioning in
the country;

(b) if so, what arc the details thereof;

(c) in what manner Government pro pose to
deal with the Degrce.vDiplomas given to the
students by these universities; and

(d) what action is contemplated by
Government against the universities func
tioning in violation of the UGC Act?

THE MINISTER OF HUMAN RE
SOURCE DEVELOPMENT (DR.
MURLI JOSHI):

(a) to (d) According to the information
turnish^d by the University Grants Com-
mission, there arc 18 self-styled and fake
universities which have come to their notice. A
list of such fake universities is enclosed is
Statcmnt-1 (*See* below. Besides these, the
Association of Indian Universities have
informed that there arc 10 more such fake
universities in the country Statement-II (*See*
below).

Section 22 of the UGC Act 1956 stipulates
that the right of conferring or granting degree
shall be exercised only by a university
established or incorporated by or under a
Central Act, a Provincial Act or a State
Act or an Institution

deemed to-be university or an Institution
specially empowered by an Act of Parliament
to confer or grant degrees. Accordingly, an
Institution not established as a university or
incorporated under an Act of Parliament/State
Legislature or granted deemed university
status or an Institution specially empowered to
award degree, is illegal ab initio and,
therefore, is not empowered to award any
degree. The operation of a fake university is
punishable under Section 24 of the Act.
Action taken under this provision against
some fake universities is in various stages in
various Courts of Law in the country.

The Parliamentary Standing Committee on
HRD have suggested in 1995 several
measures for better implementation of
measures to be taken against fake universities.
To consider these suggestions in depth, a
UGC Amendment Bill pending in Rajya
Sabha was with-drawn. These are under the
consideration of Government alongwith other
proposals for a comprehensive revision of the
UGC Act, 1956.

Statement—I

1. Maithill University/Vishwavidy-alaya,
Darbhanga, Bihar.
2. Mahila Gram Vidyapith-Vish
wavidyalaya (Women's University),
Prayag, Allahabad (U.P.)
3. Varanascya Sanskrit Vishwavidy-
aiaya, Varanasi (U.P.yiagat Puri, Delhi.
4. Commercial University Ltd.. Darya
Ganj, Delhi.
5. Indian Education Council of U.P.,
Lucknow (U.P.).
6. Gandhi Hindi Vidyapith, Prayag,
Allahabad (U.P.). '
7. National University of Electro
Complex Homeopathy, Kanpur.
8. Nelaji Subhash Chandra Bosc Uni-
versity (Open University) Aehaltal,
Aligarh (U.P.)
9. D.D.B. Sanskrit University, Putin.
Trichi. Tamil Nadu.

10. Bharatiya Shiksha Parishad (U.P.) Open Vishwavidyalaya, Lucknow, (U.P.).
11. St. John's University, Kishanattam, Kerala.
12. National University, Nagpur.
13. United Nations University, Delhi.
14. Vocational University, Delhi.
15. Uttar Pradesh Vishwavidyalaya, Kosi Kalan, Mathura (U.P.).
16. Maharana Pratap Shiksha Niketan Vishwavidyalaya, Pratapgarh, (U.P.).
17. Raja Arabic University, Nagpur.
18. Urdu University, Motia Park, Bhopal.

Statement-II

1. Akhil Bhartiya Gandhi Nisargop-char Vidyapeeth, Vijaynagar, Nanded Housing Society, Nanded- 431602.
2. Bible University, Ambur (North Arcot).
3. Eastern Orthodox University, Ambur (North Arcot).
4. Globe University of Science, Kumakonem, Tamil Nadu.
5. Mahatma Gandhi Nisargopchar Vidyapeeth Gandhi Bhavan, Kot-hrad, Pune-411029.
6. Self-Culture University, Kichant-tam, Kerala.
7. St. Ravidas Vishwavidyalaya, Munwajpur, Buiendshar, U.P.
8. Testator Research University, Bodinayakanur, Tamil Nadu.
9. University of Newjerusalm, Kuthupcrabma, Cannore, Kerala.
10. World Social Work University, Perguzhi, Kerala.

श्रीमती कमला सिन्हा : सर, दुर्भाग्य तो यह है कि हम प्रश्न पूछते हैं, सरकार सभापटल पर उत्तर रख देती है, बातें वहीं खत्म हो जाती है। मेरा प्रश्न अगर आप

देखेंगे तो उससे आपको पता लगेगा कि शिक्षा के मामले में केवल स्कूली शिक्षा में ही नहीं, उच्च शिक्षा में भी कालेज स्तर की शिक्षा में भी इस देश में एक व्यापार, अनैतिक धंधा चल रहा है। तो मेरा पहला प्रश्न सरकार से यह होगा कि क्या सरकार को जानकारी है कि इस तरह के विश्वविद्यालय निजी स्तर पर अनैतिक तरीके से, इल्लिगल तरीके से खोले जा चुके हैं, चल रहे हैं? सरकार के जवाब के हिसाब से केवल उत्तर प्रदेश में 12 विश्वविद्यालय हैं और बाकी जगहों पर भी तरह-तरह के विश्वविद्यालय हैं। इनके नाम अगर देखें जाएं तो यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी दिल्ली सरकार की नाक के नीचे हैं। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, दिल्ली, वोकेश्रल, यूनिवर्सिटी, दिल्ली, कमर्शियल यूनिवर्सिटी, दरिया गंज, दिल्ली, आदि हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार इस तरह की जो इल्लिगल यूनिवर्सिटीज चल रही है बरसों से औ जो विद्यार्थियों के जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलाड़ कर रही है, उन्हे ऊपर सरकार कौन सी कार्रवाई करने जा रही है? अब सरकार कहेगी कि यूजीसी का हमने कानून बना दिया, उसके कानून के तहत, प्रोविजन के तहत अनेक बातें हैं — सजा हो सकती है एक लाख रुपए तक की फार दि वॉरंशेन आफ दि यूजीसी एक्ट एंड यूजीसी नॉर्म्स। यह तो अपनी जगह पर है। सरकार शायद यह भी कहेगी कि कुछ लोगों के खिलाफ तो केसिस भी चल रहे हैं। लेकिन केसिस चल रहे हैं, नॉर्म्स भी है यूजीसी के, उनका वॉरंशेन भी हुआ है और यह यूनिवर्सिटीज धड़कल्ले से चल भी रही है। तो मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि सरकार इस विषय में कौन सी स्ट्रेंजेंट कार्रवाई करने जा रही है?

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले 30 विश्वविद्यालय ऐसे थे जो जाली चल रहे थे उन पर कुछ कार्रवाई की गई और वे घटकर 18 रह गए, यूजीसी के मुताबिक 10 नए विश्वविद्यालय जाली चल रहे हैं, जिसकी सूचना हमें एसोसिएशन आफ यूनिवर्सिटीज से प्राप्त हुई और इस प्रकार फिर से उनकी संख्या 28 हो गई। इसमें जो कार्रवाई की गई है, उनमें से अधिकांश के मामले कोर्ट्स में पड़े हुए हैं।

श्रीमती कमला सिन्हा : आप उसे सभापटल पर रख दीजिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी : आपका आदेश होगा तो सारे विवरण को सभापटल पर रखवा दिया जाएगा। इस प्रकार का एक विश्वविद्यालय है मैथिली युनिवर्सिटी दरभंगा। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था कि यह विश्वविद्यालय नहीं है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के तहत किसी को "विश्वविद्यालय" नाम रखने की इजाजत नहीं है लेकिन यह मैथिली विश्वविद्यालय अभी तक अपना नाम यही रखे हुए हैं। यू.जी.सी. ऐक्ट की धारा 23 और 24 के अनुसार इस पर केवल इतनी कार्यवाही हो सकती है। कि जब कोर्ट द्वारा यह बता दिया जाए कि यह विश्वविद्यालय जाली है तो उस पर केवल हजार रूपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए हजार रूपए जुर्माना देते जाड़े जाली बने रहिए। जब हमारे सामने ये बातें आईं तो इन्हें देखते हुए हमने यू.जी.सी. ऐक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए एक टास्क-फोर्स बनाई है। जिसके चेयरमैन प्रो. अमरीका सिंह हैं। इसमें और भी सदस्य हैं जैसे जी.डी. शर्मा, डी.आर. मीना और श्री एम. एम. झा इसके मेंबर सेक्रेटरी होंगे। हम कानून में पहले संशोधन करेंगे जिसकी तरफ सम्माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया है कि स्ट्रिजेट ऐक्शन लिया जाए। इसके लिए जो सिर्फ जुर्माने की व्यवस्था है, उसको बदलना पड़ेगा। इसको लागू करने का काम राज्य सरकारों का है। कोर्ट ने अभी यह डॉयरेक्शन दी है रजिस्ट्रार जिसमें "विश्वविद्यालय" शब्द का प्रयोग होता है, वह बिना यू.जी.सी. को रेफर किए न किया जाए। यह व्यवस्था तो राज्य सरकारों को ही करनी है। इसके लिए मैंने राज्य सरकारों को पत्र लिखा है कि आप यह सुनिश्चित करें कि किसी कोऑपरेटिव सोसायटी के रजिस्ट्रेशन के समय अगर उसमें "विश्वविद्यालय" शब्द का उल्लेख हो तो उसको तब तक रजिस्टर न किया जाए, जब तक कि यू.जी.सी. उसे क्लियर न कर दें और हमने राज्य सरकारों को यह भी कहा है कि ये-ये ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जिनके बारे में आपको संज्ञान कराया जाता है, आप इनके खिलाफ कार्यवाही करें।

महोदय, इसके अलावा यह भी हिदायत दी गई है कि ऐसे विश्वविद्यालयों के नाम टेलीविजन से और आकाशवाणी से प्रसारित किए जाएं और विशेषकर उस समय प्रसारित किए जाएं जब कि एजुकेशन प्रोग्राम्स प्रसारित होते हैं ताकि छात्रों को पता लगे कि इन विश्वविद्यालयों की डिग्री का कोई औचित्य नहीं है। महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा भी पता लगा है कि दिल्ली पुलिस में भी एक अधिकारी को जाली डिग्री

मिली हुई है, उसका पता लगाया जा रहा है। हमारे यहां केन्द्रीय विद्यालय संगठन में भी एक अध्यापक को जाली डिग्री के आधार पर नौकरी दी गई है। उस पर हम ऐक्शन ले रहे हैं। तो यह समस्या पिछले कई सालों से चली आ रही है। पिछले एक-दो महीने में जो कार्यवाही की जा सकती थी, वह मैंने आपके सामने रख दी है। यदि आपके इस बारे में कोई सुझाव हों कि कानून में ओर क्या परिवर्तन करना चाहिए तो उन्हें आप कमेटी को भेजिए। सरकार को भेजिए, हम निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। महोदय, सारा देश और सारा सदन इस बात से सहमत होगा कि इस बारे में कोई कड़ी से कड़ी कार्यवाही जरूर की जानी चाहिए और हम करेंगे।

श्रीमती कमला सिन्हा : सभापति महोदय, मंत्री जी ने बड़ी सफाई से बातों को कहा है क्योंकि इसमें बातें छिपानेकी गुंजाइश नहीं थी।

डा. मुरली मनोहर जोशी : ये मंत्री और सरकार बातें छिपाते नहीं हैं। वे जमाने चले गए।

श्रीमती कमला सिन्हा : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूँ कि हम सब लोग जानते हैं कि जब किसी काम को टालना होता है, किसी विषय को टालना होता है तो उसके ऊपर एक कमेटी बना दी जाती है या टास्क-फोर्स बना दी जाती है और टास्क-फोर्स इक्वायरी कर रही है, कमेटी इक्वायरी कर रही है, ऐसा कहा जाता है। फिर उसकी रिपोर्ट आती है, सदन में पेश होती है, सरकार उस पर विचार करती है लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं हो पाती है। मैं सरकार से यह कहना चाहती हूँ कि टास्क-फोर्स का काम अपनी जगह पर है लेकिन सरकार को मालूम है कि 18 विश्वविद्यालय नाजायज तरीके से चल रहे हैं, जो अपने को विश्वविद्यालय कहते हैं लेकिन जो सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के तहत रजिस्टर होकर काम कर रहे हैं और नाजायज तरीके से बच्चों की जिंदगी और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मंत्री जी ने कहा कि नए और 10 बढ़ गए हैं। यानी 30 पहले थे, उसके बाद कुछ कम हुए और फिर अब 28 हो गए हैं। यानी वही ढाक के तीन पात। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार एक कठोर कानून इस बारे में लाना चाहती है?

अब मैं जानना चाहती हूँ कि सरकार क्या एक कठोर कानून इस विषय में लाना चाहती है और अगर लाना चाहती है सदन में तो कब तक लाना चाहती है? सरकार कब तक लाना चाहती है इसका टाईम फ्रेम भी बता दें कि कितने दिन के अंदर करना चाहती है और इस कानून के जरिए क्या यह अनैतिक धंधा बंद कराने की सरकार की मंशा है?

3j **डा. मुरली मनोहर जोशी :** सभापति जी, मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि यह टास्क फोर्स कानून बदलने के लिए ही बनाई गई है और उसको बताया गया है कि कानून में ऐसे संशोधन करें जिससे इस प्रकार के विश्व विद्यालयों का चलना असंभव हो जाए। लेकिन सदन यह तो स्वीकार करेगा कि हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें लॉ मिनिस्ट्री का सहयोग होना जरूरी है, उनकी राय जरूरी है। कानून बनाने के लिए शिक्षाविद्, लॉ मिनिस्ट्री और यू.जी.सी. के पुराने सैक्रेट्री सबको रखा गया है। इसीलिए रखा गया है कि वह कानून बनाएं। यह टास्क फोर्स कोई विश्व विद्यालय चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है इसकी जानकारी करने के लिए नहीं है परन्तु यह कानून किस तरह से कड़े से कड़ा बनाया जाए उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए इसके लिए है दिक्कत आज इम्प्लीमेंटेशन की आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह विश्व विद्यालय अपने नाम के आगे विश्व विद्यालय नहीं लिख सकते लेकिन विश्व विद्यालय लिख रहे हैं। अब इस पर कार्रवाई तो राज्य सरकारों को ही करनी पड़ेगी। राज्य सरकार कहती है कि यह जी यू.जी.सी. का कानून है इसमें केवल हजार रुपए जुमाने की बात है, यानी आप हजार रुपए साल देते रहिए और जाली बने रहिए। उस कानून को बदलने के लिए ही यह किया गया है कि वह जल्दी से जल्दी कानून को बदलकर लाएं। एच.आर.डी. की जो हमारी स्थाई समिति है उससे भी सलाह होगी क्योंकि बिना उसकी राय के कानून नहीं बन सकता। इसलिए कानून बनाने की जो प्रक्रिया है और उसमें जो सबसे अल्प अवधि की प्रक्रिया है हम उसी को लेंगे।

श्रीमती कमला सिन्हा : एच.आर.डी. की स्थाई समिति की रिपोर्ट आ चुकी है। उसने भी रिकमंड किया है कि वह कानून बनना चाहिए, सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि सरकार सीधा-सीधा जवाब क्यों नहीं देती है कि कानून कब तक बनाएगी, कब तक इस सदन में, उस सदन में कानून लाएगी, यह बता दें? When this Act is going to be brought and when this Act is going to be implemented?

डा. मुरली मनोहर जोशी : जैसे ही इस टाक्स फोर्स की रिपोर्ट आ जाएगी हम कानून बनाएंगे।

श्री जनार्दन यादव : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह जो 28 फर्जी विश्व विद्यालय हैं इसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज कितने हैं और उन कॉलेजों से जो लड़के पास हुए हैं, जिनको डिग्री मिली है, क्या उन डिग्रीयों को

वर्तमान सरकार ने या पिछली सरकार ने मान्यता दी है? एक हजार रुपया जुमाना देने से तो वह विश्वविद्यालय चलेगा। लेकिन ऐसे विश्व विद्यालयों से जो डिग्री आज तक मिली है और उन डिग्रीयों के आधार पर जो नौकरी में चले गए होंगे उनके बारे में माननीय मंत्री जी क्या कार्रवाई कर रहे हैं?

डा. मुरली मनोहर जोशी : जिनको वह डिग्री मिली है और यहां यह पता लगता है, क्योंकि हम तो केवल सभी संस्थाओं को यह सूचित करते हैं कि विश्व विद्यालय आत है और उनकी अधिक से अधिक सूचना प्रसारित हो इसलिए टेलीविजन और आकाशवाणी दोनों को यह सलाह दी गई है, उनसे निवेदन किया गया है कि इनके नाम बार-बार प्रसारित किए जाएं और उस प्रसारण में यह भी कहा जाएगा कि इस डिग्री के आधार पर कोई नौकरी न ले और अगर किसी को इस डिग्री के आधार पर नौकरी में लिया गया है तो उसकी नौकरी रिस्तर पर नौकरी में लिया गया है तो उसकी नौकरी निरस्तर कर दी जाए। मैंने बताया कि जैसा केन्द्रीय विद्यालय संगठन में हमें पता लगा तोहम उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। जहां तक इसका सवाल है, इन विश्व विद्यालयों के बारे में अभी सरकार के पास कोई जानकारी इनजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज की तो नहीं आई है। तीसरी बात जो उन्होंने कही है कि इन विश्व विद्यालयों से प्राप्त डिग्रीयां जो चल रही है वह तो कानून की खामी के कारण चल रही है और कानून की खामी हम ठीक करेंगे और उसे दुरुस्त करेंगे और जल्दी से जल्दी इन जाली विश्व विद्यालयों का चलना हम बंद करेंगे। यह अनेक वर्षों से चल रहा है, हाल ही में नहीं आए है। हमारे सामने जैसे ही एच.आर.डी. की रिपोर्ट आई कार्रवाई शुरू की ओर निश्चित रूप से यह टास्क फोर्स बहुत प्रमाणिक ढंग से काम करेगा और प्रोफेसर अमरीक सिंह के बारे में सारा सदन जानता है, सारा देश जानता है कि वह शिक्षा के मामले में यू.जी.सी. के मामले में बहुत एक्सपर्ट है और सब मामलों में बहुत संजीव राय रखते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि उनके द्वारा बनाया गया कानून बहुत इफेक्टिव होगा

DR. KARAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, the fact is, fake universities are indeed a very reprehensible thing because they are playing with the future of young peoples' lives, misleading them and leading them into a great difficulty. I would like to ask the hon. Minister a question arising out of this. The idea that a 'university has got to be a Suite's monopoly, that only by an Act of Parliament

or only by an ate legislature can. a university be set up is to my mind outmoded idea. Sir, the educating nology is now developing very repudly There is distance education. There is satelfitc education. There was a proposal for private universities. A Bill was drafted. If i understand correctly, there was a Select Committee. Shri P. Upend-ra., who was then a Member of this House, was the Chairman of that Select Committee. I gave evidence before it. The idea was that since there were i of private institutions, a lot of jsors-offical institutions, which had the cap,-wSiich had the technology to provide top class education, who this old idea of State monopoly should continue. May i ask the hon. Minister what has become of that Private Universities Bill? When is it to be brought before "he Parliament? Will this Government fully support it? Fake universities come up because of the tre-menJom- desire of young people to learn. If there are other opportunities available, why should they not be allowed to avail themselves of those opportunities? Why should they be deprived of that?

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, a draft of the Bill is there and it is under active consideration of the Government.

DR. KARAN SINGH: Sir, the Select Committee has submitted its report. Now, is that Bill coming before this House? Is it going to be introduced in this session or the next session? This is a matter of some urgency because we are dealing with young people, whose whole lives are before them and whose entire career cc-ald be destroyed by these sort of repiertsensible activities.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, there are several aspects of this Bill and we are taking into account all the aspects so that when the Bill is placed before the House it results in a very fruitful Act and it serves the purpose very effectively. So, we are taking adequate steps and I am sure that the House will be informed about this Bill very soon.

DR. RAJA RAMANNA: Mr. Chair-n. Sir, I have noticed that in these fake colleges and fake universities the *modus operandi* is, first start a college, get a lot of people admitted and then try to get recognition. At this stage when the students are already suffering, and most of them are foreign students, you cannot do much. The students say that they have paid a lot of money. They have come from far off countries and joined this coHcge. And now you want to close the college. What should they do? It is very important that you should start dealing with fake colleges at an early stage and not when things have reached a stage where you cannot do anything. There are many colleges, like the dental colleges, in my own city of Bangalore, which are constantly doing this. The money accepted from the candidates goes in to several lakhs of rupees, and then the man runs away. So, may I suggest to the hon. Minister that there should be almost a police force for watching these institutions, and striking at the very roots in the beginning when they start, rather than at a stage when the whole thing becomes too late and things go to court and so on. Thank you.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, this is a suggestion which will be taken into consideration without fail. But, we are no.w strengthening the accreditation system. Even today it is not that only the so-called fake universities and fake colleges are not accredited* but many of the old universities also have not been accredited. The accreditation system is not strong enough. There is an Accreditation Committee and an Accreditation Council, which are without any proper infrastructure. So, we have now decided to strengthen it and we are taking measures in consultation with the UGC so that accreditation becomes very meaningful and only accredited colleges and universities run in this country. If anybody takes admission in such institutions which are not accredited, it will be at his own risk.

We will certainly take into consideration this suggestion. We will take action against those fake colleges which are running even today and also those which have been closed, if they have been given permission by the UGC or the AICTE. If they are running without their permission, then we are helpless. But, if they have been given permission by these bodies, then certainly we will look into this matter.

DR. M. N. DAS: Sir, while the UGC at long last has been able to detect and identify some of the fake universities in the country, I would like to know whether the UGC and the Ministry of HRD are aware of the fact that there are some genuine and reasonable demands from some regions of some States for establishment of new universities, and, if so, what policy has been formulated on a definite basis so that universities could be opened where the demands are genuine.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: This is between the State Government and the UGC. If the State Government has the necessary funds and requirements, and satisfies the norms of the UGC, then there is no bar from the Ministry to any State opening a university.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जिन-जिन यूनिवर्सिटी का जिक्र किया है इसके अलावा आयुर्वेदिक की, यूनानी की, होम्योपैथी की, स्पोर्ट्स की, फिजिकल एजुकेशन के नाम पर देशभर में सैकड़ों यूनिवर्सिटीज और कालेज चल रहे हैं। उनके प्रतिदिन अखबारों में इशतहार दिए जाते हैं और लाखों आदमियों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मंत्री महोदय ने इस बारे में जो चिन्ता प्रकट की है वह प्रशंसनीय है। परन्तु केवल एक हजार रुपये का जो जुर्माना है उसको बढ़ाकर एक लाख या 10 लाख करने में या सजा का प्रावधान करने में क्या किसी कमेटी की जरूरत है? अगर उनको कड़ी सजा देनी है तो कड़ी सजा तो कोई भी सीधे तौर पर कर सकता है। एक हजार रुपये के बजाय उसका जुर्माना इतना होगा या इतनी सजा होगी क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे? कमेटी की रिपोर्ट पता नहीं कब आएगी? क्या अखबारों में इसका इशतहार देने पर कोई प्रतिबंध लगाया जाएगा?

डा. मुरली मनोहर जोशी : सर, जहां तक चिकित्सा के क्षेत्र के विश्वविद्यालयों का सवाल है तो चिकित्सा का क्षेत्र हमारे मंत्रालय के अधीन नहीं है। उसके बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय के पास जो जानकारी होगी उसके ऊपर वहां से कार्रवाई की जाएगी। अगर स्पोर्ट्स के बारे में किस ने जाली विश्वविद्यालय की रचना की है तो इसकी हमारे पास कोई सूचना नहीं है और सूचना मिलने पर हम जरूर उनके खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे। केवल हजार रुपये से, लाख रुपये से या 50 हजार रुपये या दो लाख रुपये का जुर्माना दे देना, इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसमें कानून की कई डाइमेंशन्स हैं। इसमें राज्य सरकारों से भी सलाह लेनी पड़ेगी, उनको अपने रजिस्ट्रेशन के कानून में भी तब्दीली करनी पड़ेगी। उस कानून के अन्तर्गत क्या-क्या किया जा सकता है इस पर भी हम उन्हें सलाह देंगे क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करना है, यह सब उनके हाथ में रहेगा। प्रोसीक्यूशन जिस-जिस लेवल पर करना है वह राज्य सरकारों के माध्यम से ही होगा। इसलिए कानून में ऐसी व्यवस्थाएं करने होंगी। केवल जुर्माने का ही सवाल न ही बल्कि सजा दी जाए और वह किस तरह से दी जा सकती है, उसमें कोई भी लूपहोल न रहें, उसमें कोई भी क्षेत्र ऐसा न बचे जिसका लाभ उठाकर जाली विश्वविद्यालय चल सके। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि डा. अमरीक सिंह इस मामले में बहुत ही एक्सपर्ट हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं, उनकी बनाई हुई कमेटी से आप यह आशा करेंगे कि वह बहुत शीघ्रता से इस काम को करेंगे। आप भरोसा रखिए हम जल्दी से जल्दी इस मामले में कदम उठाएंगे। हमने उनको केवल 30 दिन का ही समय दिया है और आप यह समझें कि जितनी जल्दी हम इसको कर सकते हैं, वह करेंगे।

"Underground Mineral Resources in Forests

*342. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are large amounts of underground mineral resources in areas which are forested;

(b) whether State Governments are putting pressure to destroy forest area for development projects; and

(c) what action Government are taking to protect the limited area of forests from such developmental activity?